

“ग्रामीण युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान” एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

दिलीप तिवारी*

सार

वर्तमान समय में भारत देश में ग्रामीण युवा वर्ग में बेरोजगारी की समस्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने इस बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाया जिसके अंतर्गत देश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने युवा वर्ग रोजगार प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत देश के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने का कार्य किया जाता है वास्तव में भारत की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है जिसमें से लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। जहाँ कौशल प्रशिक्षण का अभाव सदैव देखा गया है इस योजना के माध्यम से सरकार का यह प्रयास है वह ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके लिए कारगर रोजगार की व्यवस्था कर सके ताकि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। प्रस्तुत शोध के माध्यम से शोधार्थी ने ग्रामीण युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान जानने का प्रयास किया है।

शब्दकोष: ग्रामीण, बेरोजगारी, युवा, कौशल विकास, रोजगार, प्रशिक्षण, जनसंख्या।

प्रस्तावना

भारत के युवाओं में कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रारंभ किया ताकि भारत के ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार नवयुवकों को सक्षम बनाकर रोजगार से जोड़ा जा सके इस योजना की शुरूआत 15 जुलाई 2015 को की गई। योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण तथा शहरी नवयुवक को रोजगार दिलाना तथा मुफ्त में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान कराकर स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित किया जाता है। योजना के लिए राज्य सरकारे अपने शहरों में ई – प्रशिक्षण केन्द्र खोलती है ताकि समस्त ग्रामीण व शहरी शिक्षित नवयुवक को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा सके। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में राज्य सरकारे केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर देखरेख का कार्य करती है। ये योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है इस मंत्रालय का मुख्य कार्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का निर्णय किया जाना है ताकि ये युवक इन अवसरों में से अपना पसंदीदा अवसर चुनकर अपना भविष्य संवारते हैं। प्रस्तुत शोध रीवा जिले के ग्रामीण युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान स्पष्ट करता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन युवाओं को लाभ दिलाया जाता है जो दसवीं तथा बारहवीं तक की पढ़ाई उत्तीर्ण करके पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। तथा उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं

* शोधार्थी, शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

होता है। कुछ युवा गरीबी के कारण या अन्य किसी कारण वश पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण दे कर उन्हे रोजगार दिलाया जाता है प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान कराया जाता है। ये प्रमाण – पत्र रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। इस योजना के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण समस्त शिक्षित युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। योजना का बजट रु 12 हजार करोड़ रखा गया है योजना के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्तमान समय में 32000 प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तीन चरणों में विस्तारित है –

- प्रधानमंत्री कौशल विकास 1.0
- प्रधानमंत्री कौशल विकास 2.0
- प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0

प्रथम चरण 15 जुलाई 2015 से प्रारंभ किया गया था जिसकी अवधि केवल 2015–16 ही थी। इस चरण में युवाओं को मुफ्त लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा मौद्रिक पुरस्कार के द्वारा कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जात है। इसमें रोजगार मेला विशेष परियोजना प्रशिक्षण आदि को शामिल किया जाता है। योजना अवधि में 19.85 लाख हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

दूसरा चरण अवधि 2016 –2020 तक की है। इस चरण में अधिक संख्या में युवाओं को उद्योग के अनुकूल गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम बनाया गया ताकि वे रोजगार परक बनकर आजीविका चला सकें। इसमें मैंक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि मिशनों को शामिल किया गया है। इस योजना चरण का कुल बजट रु. 12 हजार करोड़ था। योजना चरण में 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

तीसरा चरण अवधि 2020–21 तक था। यह चरण 717 जिलों, 28 राज्यों तथा 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ लागू किया गया। योजना चरण के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत मिशन लाया गया जिसमें माध्यम से युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। योजना चरण के अंतर्गत देश के युवाओं को रोजगार के लिए कौशल का गुण सिखाया गया ताकि ये युवा अपकी आजीविका का साधन बना सकें। योजना में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इस योजना चरण में कुल बजट 948.90 करोड़ था तथा 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया था। योजना के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा समग्र विकास, युवाओं को वोकल फार लोकल अभियान से जोड़ना तथा SSC द्वारा मूल्यांकन कर प्रमाण— पत्र वितरित करना आदि कार्य किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है:—

- भारत का मूल निवासी हो।
- दसवीं बारहवीं उत्तीर्ण हो
- आय का कोई साधन न छोड़े
- हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो।

योजना के अंतर्गत किए गए पाठ्यक्रम निम्न हैं:—

- रबर कोर्स
- प्लम्बिंग कोर्स
- माइनिंग कोर्स
- रिटेल कोर्स
- इंटरटेनमेंट मीडिया कोर्स

- लाइफ साइंस कोर्स
- टूरिज्म कोर्स
- कृषि कोर्स
- बीमा बैंकिंग कोर्स
- फाइनेंस कोर्स
- निर्माण कोर्स
- मोटर वाहन कोर्स
- इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स
- ग्रीन जॉब कोर्स
- फूड प्रोसेसिंग कोर्स आदि।

शोध समीक्षा

दास, दीपक कुमार 2020 द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र “प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान” में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताया है तथा उसमें योगदान भी स्पष्ट किया गया है निष्कर्ष के रूप में यह बताया गया है कि यह एक कौशल पर आधारित योजना है जिसमें प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार दिलाया जाता है।

रस्तोगी, रवि 2017 द्वारा प्रस्तुत शोध— पत्र भारतीय ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना का प्रभाव एक अध्ययन” में यह बताया गया है कि कौशल विकास योजना का प्रभाव भारतीय ग्रामीण युवाओं पर पड़ता है इस योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्रामीण युवा वर्ग लाभान्वित हो रहा है। ग्रामीण युवा रोजगार तथा स्वरोजगार की ओर अग्रसर है।

भारती, रवि 2018 द्वारा प्रस्तुत शोध— पत्र युवा वर्ग के विकास में कौशल विकास योजना तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भूमिका में यह बताया गया है कि युवा वर्ग को रोजगार से जोड़ने का एक मात्र साधन कौशल विकास ही है जिसके अंतर्गत मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रयोग करके युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बताया जा रहा है।

शोध का उद्देश्य

शोध पत्र अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:-

- कौशल विकास योजना का मूल्यांकन करना।
- कौशल विकास योजना का ग्रामीण युवाओं के कौशल पर प्रभाव का अध्ययन।
- बेरोजगार ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना के योगदान का अध्ययन करना।
- कौशल विकास योजना से स्वरोजगार पर प्रभाव का अध्ययन

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध – पत्र ‘ग्रामीण युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान :- एक अध्ययन से संबंधित निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:-

- ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है।
- ग्रामीण युवाओं में शिक्षा का स्तर कम है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु समंकों का संकलन प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर साक्षात्कार तथा अनुसूची द्वारा प्राथमिक समंक एकत्र किए गए हैं। तथा कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र – पत्रिका बुलेटिन तथा आकड़ों द्वारा द्वितीयक समंक एकत्र किए गए। इसके साथसाथ इंटरनेट को विभिन्न साइटों द्वारा भी द्वितीयक समंक एकत्र किए गए। एकत्र किए गए प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों को सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा वर्गीकृत करके उन्हें सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हुए विश्लेषण करके परिणाम निकाला जाता है।

समंको का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन के दौरान प्राथमिक तथा द्वितीयक संमंकों का उपयोग किया गया है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है:—

प्राथमिक समंको का विश्लेषण :—

प्राथमिक समंकों का संग्रहण प्रश्नावली से किया गया है। जिसमें 50 लोगों से प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। इनका विश्लेषण इस प्रकार है:—

ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी है:—

तालिका 01

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	हॉ	20	40%
02	नहीं	30	60%
	कुल	50	100%

स्त्रोत :— सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़े

तालिका 01 से स्पष्ट है कि रीवा जिले में 40% ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी है तथा 60% युवाओं को जानकारी ही नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है:—

तालिका 02

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	हॉ	35	70%
02	नहीं	15	30%
	कुल	50	100%

स्त्रोत :— सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़े

तालिका 02 से स्पष्ट है कि रीवा जिले के 70% ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों का मानना है कि यहाँ प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है तथा 30% निवासियों का मानना है कि यहाँ पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्र है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है:—

तालिका 03

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	हॉ	40	80%
02	नहीं	10	20%
	कुल	50	100%

स्त्रोत:— सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़े

तालिका 03 से स्पष्ट है कि रीवा जिले के 80% ग्रामीण निवासी यह मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है जबकि 20% निवासियों का मानना है कि योजना का संचालन सही तरीके से हो रहा है।

ग्रामीण युवाओं में शिक्षा का स्तर कम है:-

तालिका 04

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
01	5वीं	05	10%
02	8वीं	10	20%
03	10वीं	15	30%
04	12वीं	20	40%
कुल		50	100%

स्रोत :- सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आकड़े

प्रस्तुत तालिका 04 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण युवाओं में 40%, 12वीं उत्तीर्ण है 30%, 10 वीं उत्तीर्ण है 20%, 8वीं उत्तीर्ण है तथा 10%, 5वीं उत्तीर्ण है। इससे यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा स्तर कम नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पात्रता रखने वाले युवाओं का प्रतिशत 40% है इससे स्पष्ट है कि युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

द्वितीयक समंको का विश्लेषण

रीवा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नामांकित उम्मीदवार तथा प्रशिक्षित उम्मीदवार की संख्या इस प्रकार है:-

तालिका 05

क्रमांक	योजना का नाम	नामांकित	प्रशिक्षित	प्रतिशत
01	PMKVY 1.0 (2015 - 16)	2979	2979	100%
02	PMKVY 2.0 (2016 - 20)	14801	14465	97.7%
03	PMKVY 3.0 (2020 - 21)	1321	1289	97.5%

स्रोत:- PMKVY official.org

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 05 से स्पष्ट है कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत PMKVY 1.0 (2015 - 16) में 100% उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया PMKVY 2.0 (2016 - 20) में 97.7% उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा PMKVY 3.0 (2020 - 21) में 97.5% उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया इससे स्पष्ट है कि ये योजना पूर्णतः सफल सिद्ध हो रही है।

रीवा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों में मूल्यांकित प्रमाणित तथा रिपोर्टेड व प्लेसमेट प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:-

तालिका 06

क्रमांक	योजना का नाम	मूल्यांकित उम्मीदवार	प्रमाणित उम्मीदवार	रिपोर्टेड उम्मीदवार	प्लेसमेट
01	PMKVY 1.0	2949	2450	631	25-75%
02	PMKVY 2.0	13117	11249	5577	49-57%
03	PMKVY 3.0	1114	673	89	13-22%

स्रोत:- PMKVY official.org

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 06से स्पष्ट है कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत PMKVY1.0 में प्लेसमेट प्रतिशत 25.75% PMKVY 2.0 में प्लेसमेट प्रतिशत 49.57% तथा PMKVY 3.0 में प्लेसमेट प्रतिशत 13.22% है इससे यह स्पष्ट होता है कि युवा वर्ग प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लेता है किन्तु रोजगार की ओर से मुँह मोड़ लेता है। अर्थात् युवा वर्ग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेकर रोजगार बहुत कम प्राप्त करता है।

परिणाम

प्रस्तुत शोध—पत्र के अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक समंको में विश्लेषण के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त किए गए:—

- ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी का अभाव है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संचालन में लापरवाही है।
- ग्रामीण युवाओं में शिक्षा का स्तर उत्तम है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्लेसमेट प्रतिशत बहुत कम है।

सुझाव

प्रस्तुत शोध—पत्र के अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त परिणामों के आधार पर सुझाव इस प्रकार है:—

- ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी पर्याप्त मात्रा में देने के लिए योजना का प्रचार — प्रसार करना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी को दूर करना चाहिए ताकि ग्रामीण युवा योजना का लाभ ले सके।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालक ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से करना चाहिए।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्लेसमेट को बढ़ाने हेतु सरकार को प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत शोध—पत्र "ग्रामीण युवाओं पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का योगदान" — एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) अध्ययन के दौरान इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ग्रामीण युवाओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बात की पुष्टी के लिए निर्धारित परिकल्पनाओं का सत्यापन सारणी के द्वारा किया गया है।

जिसमें परिकल्पना क्रमांक 01 से हमें यह पता चला है कि 60% ग्रामीण युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी ही नहीं है तथा 40% युवाओं को जानकारी है।

परिकल्पना क्रमांक 02 से हमें यह पता चला है कि 70% ग्रामीण युवाओं का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव है तथा 30% लोगों का मानना है कि प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त है।

परिकल्पना क्रमांक 03 से हमें यह पता चला है कि 80% ग्रामीण युवाओं का मानना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में सही तरीके से नहीं हो रहा है। तथा 20% का मानना है कि हो रहा है।

परिकल्पना क्रमांक 04 से हमें यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना हेतु आवश्यक शिक्षा का स्तर अच्छा है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12वीं उत्तीर्ण 40% तथा 10वीं उत्तीर्ण 30% युवा है।

अतः प्रस्तुत परिकल्पनाओं में परिकल्पना क्रमांक 01 तथा 04 आंशिक रूप से असत्य है तथा परिकल्पना क्रमांक 02 तथा 03 सत्य है।

प्रस्तुत अध्ययन से इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करके प्लेसमेंट नहीं लेते हैं।

सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो कमियों हैं उन्हें दूर करके रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं पर अपना योगदान सुनिश्चित करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दत्त गौरव व महाजन अशिवनी (2016) – भारतीय अर्थव्यवस्था, एस चॉद एण्ड कम्पनी, दिल्ली पृष्ठ संख्या 275।
2. आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार वित मंत्रालय (2016–17)
3. योजना पत्रिका 2022
4. कुरुक्षेत्र पत्रिका 2022
5. PMKVY official.org
6. Skillindia.gov.in
7. दैनिक भास्कर रीवा

